STATEMENT BY MINISTER - *Contd.*

Avalanche in Chamoli district of Uttarakhand

MR. CHAIRMAN: Friends, we have another important responsibility today that is about Statement by Minister. Shri Amit Shah to make a Statement regarding an avalanche in Chamoli District of Uttarakhand.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): सभापति महोदय, एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का ब्यौरा अपने स्टेटमेन्ट के द्वारा सदन के समक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

दिनांक 07.02.2021 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के ..**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आज़ाद जी, अभी भी रहेंगे, 13 तारीख तक सदन में हैं।

श्री अमित शाहः ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई बाढ़ से 13.2 मेगावॉट की कार्यरत छोटी जलविद्युत परियोजना पूरी बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौलीगंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावॉट की जलविद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है।

उत्तराखंड सरकार ने यह बताया है कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जलस्तर में भी कमी आ रही है। केन्द्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं।

7 फरवरी, 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्रतल से लगभग 5,600 मीटर ऊपर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो कि लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ़्लड की स्थिति बन गई।

उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं - यह आंकड़ा, महोदय, मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूं तो कल शाम पांच बजे तक का है, वह बदलता रहता है - 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता हैं, जिनमें एनपीटीसी की निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषिगंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति

और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है।

1.00 P.M.

एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अन्दर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषिगंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में अंदाज़न लगभग 25 से 35 लोगों के फँसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फँसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूँढ़ने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गँवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गाँवों से एक पुल बह जाने के कारण सम्पर्क बिल्कुल कट गया है। इन गाँवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलिकॉप्टर द्वारा लगातार पहुँचाया जा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति की चौबीसों घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर चौबीसों घंटे नज़र रखी जा रही है और राज्य को हर सम्भव सहायता मुहैया करायी जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायज़ा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहाँ स्थापित कर लिया है और उसके 450 जवान सभी जरूरी साज़ो-सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुँच चुकी हैं तथा राहत और बचाव अभियान में लगी हुई हैं। आर्मी की आठ टीमें, जिनमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रही है। एक मेडिकल कॉलम और दो एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात हैं। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गयी है। एयरफोर्स के 5 हेलिकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरन्त शुरू कर दिया गया था। टनल में फँसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात-भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुँह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है, काफी अन्दर तक हमारे लोग गये हैं। केन्द्रीय जल आयोग के जो कर्मचारी अलकनन्दा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत हैं, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुँच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम, जो हिमस्खलन की निगरानी करती है, घटनास्थल पर वह भी पहुँच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं।

नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही साढ़े चार बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी सम्बन्धित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

केन्द्रीय एजेंसियों के साथ-साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। एसडीआरएफ की दो टीमें भी राहत और बचाव में कार्यरत हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलिकॉप्टरों को भी बचाव और राहत कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गयी है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है।

मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) से लगभग 1,041 करोड़ रुपये उत्तराखंड के लिए आवंटित किये गये हैं, जिसमें केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त, already 468.50 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को जारी की जा चुकी है।

मैं सदन को केन्द्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी सम्भव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किये जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाने जरूरी हैं, वे सभी कदम उठाये जा रहे हैं।

मैं सभी मृतकों के लिए अपनी ओर से, सदन की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: I request all the Members to rise in their places and observe silence in memory of those departed.

(Hon. Members then stood in silence for one minute.)

MR. CHAIRMAN: We pray for their soul to rest in peace, and also hope that the other people who are all affected by this, the rescue operations will succeed and their lives can be saved. And as and when we get further information, we will try to discuss it.